(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(ङ) क्या सरकार जिन संयंत्रों से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूल किया गया है, उन्हें वह लौटा देगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्टिकल शाफ्ट किल्न अथवा रोटेरी किल्न का प्रयोग करते हुए किसी कारखाने में विनिर्मित सीमेंट पर, जिसकी संस्थापित अथवा लाइसेंससुदा क्षमता विनिर्दिष्ट की गई होती है, 165/- रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से मूल उत्पाद शुल्क लगाया जाता है । अन्य संयंत्रों में विनिर्मित सीमेंट पर 290/- रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से मूल उत्पाद शुल्क लगाया जाता है ।

(ग) वर्टिकल शाफ्ट किल्न अथवा रोटेरी किल्न का प्रयोग करने वाले सीमेंट पर मुख्यत: निम्नलिखित कारणों के आधार पर उत्पाद शुल्क की निम्न दर लागू की गई है :—

(i) दुर्गम्य क्षेत्रों में उपलब्ध चूने के पत्थर के छोटे-छोटे भण्डारों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए;

(ii) चूने के पत्थर के छोटे-छोटे भण्डारों वाले क्षेत्रों में और उनके आस-पास छोटे-छोटे बाजारों की स्थापना करके इसका व्यापार बढ़ाने के लिए ।

(घ) से (च) आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर कोई ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के दायरे में लाया जाना

121. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के दायरे में लाने का विचार रखती है?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के म्यूचुअल फंडों से संबंधित क्रियाकलापों को सेबी के दायरे में लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Liberalisation of Rules for Attracting Foreign Investment

122. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of the steps Government have taken from time to time to liberalise the rules for attracting foreign investment in the country.

(b) what is the impact of the rules on the inflow of foreign investment during the years 1991 and 1992;

(c) whether Government propose to further liberalise the rules in this regard; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND